बच्चों के लिए ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करने जा रहा है जिनसे उनमें राष्ट्रीय एकता तथा अनुशासन की भावना जाग्रत हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना के कब तक क्रियान्वित हो जाने की सम्भावना है ?

†[CHILDREN BOOKS

1377. SHRIMATI VIDYAWATI CHATURVEDI: Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry of Education and the National Book Trust propose to publish books for children in the near future with the aim of infusing in them the spirit of national integration and discipline; and

(b) if so, by when the scheme in this regard is expected to be implemented?]

शिक्षा तथा युवा सेवा मंत्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां, बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना को भरने के लिए, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सहयोग से, बच्चों के लिए अनुपूरक सामग्री तैयार करने हेतु "नेहरू बाल पुस्तकालय" नामक एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ख) योजना विचाराधीन है और कार्यान्वयन के लिए इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ।

†[THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (PROF. V. K. R. V. RAO): (a) Yes, Sir in order to promote national integration among children, a scheme entitled 'Nehru Bal Pustakalaya' for the production of supplementary reading material for children is proposed to be initiated in collaboration with the National Book Trust.

(b) The scheme is under consideration and is expected to be finalised for implementation soon.]

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति

1378. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उच्च न्यायालयों के और न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

†[APPOINTMENT OF HIGH COURT JUDGES

1378. SHRI SURAJ PRASAD: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state whether there is any proposal under Government's consideration to appoint more High Court Judges?]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। संस्थापनाओं, निपटानों तथा लम्बित पड़े मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में यथावश्यक वृद्धि करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजना राज्य प्राधिकारियों का काम है ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): There is no such proposal under consideration of the Government of India. It is for the State authorities to review the judge strength in each High Court with reference to the institutions, disposals and arrears to be cleared and to send proposals to the Government of India for augmentation of the judge-strength to the extent considered necessary.]

†[ ] English translation.